Toppersnotes
Unleash the topper in you

UK – PCS

State Civil Services

Uttarakhand State Combined Civil/Upper Sub-Ordinate Exam

(Preliminary & Main)

पेपर – 2 भाग – 2

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं संगठन

SIERRA INNOVATIONS

विषय सूची

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध एवं संगठन

1.	शीत युद्धोत्तर	1
2.	संयुक्त राष्ट्र संघ	7
3.	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियाँ	21
4.	भारत की विदेश नीति	27
5.	भारत-यू.एस.ए. संबंध	36
6.	भारत-चीन संबंध	49
7.	भारत-रूस संबध	63
8.	यूरोपीय संघ	69
9.	गुट निरपेक्ष आन्दोलन (**NAM**)	76
10.	**Brics**	79
11.	**G-77**	85
12.	सार्क	86
13.	आसियान	91
14.	भारत-श्रीलंका संबंध	104
15.	भारत-अफगानिस्तान संबंध	108
16.	भारत - बांग्लादेश संबंध	111
17.	भारत - मालदीव संबंध	116
18.	भारत - नेपाल संबंध	118

19.	पश्चिमी एशिया	122
20.	दक्षिणी–पूर्वी एशिया	133
21.	भारत फ्रांस संबंध	136
22.	भारत – जर्मनी संबंध	139

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

Unleash the topper in you

1. शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वि-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हुई जिसमें अमेरिका एवं सोवियत संघ दो महाशक्तियों का उदय हुआ । लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गई। शीत युद्ध का प्रतीक रही बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा दी गई और समसामयिक विश्व में नई विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। शीत युद्ध के अन्त ने अमेरिका को इकलौती महाशक्ति बना दिया। यह एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका द्वारा संचालित था । अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केन्द्र हो तो इसे 'वर्चस्व' शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित होगा। इस प्रकार सन् 1991 के बाद के काल को अमेरिकी वर्चस्व दौर कहा जाता है।

वर्चस्वः- वर्चस्व का अर्थ किसी एक देश की अगुआई या प्रावल्य है। वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है । इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अर्थात जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का केन्द्र एक हो तो उसे वर्चस्व नाम देना उचित होगा।

विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की अभिव्यक्ति निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं एवं प्रवृत्तियों में होती है।

अमेरीकी वर्चस्व का इतिहास कोई नया नही है। सोवियत विभाजन से पहले भी अमेरिका के द्वारा विश्व परिदृश्य पर अनेक ऐसे कदम उठाए गए थे जो उसके वर्चस्व को दर्शाते है।

खाडी युद्धः- कुवैत तेल उत्पादक देश है कुवैत के तेल ईंधन पर कब्जा करने के लिए 2 अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बडी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया । इराक को समझाने-बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल-प्रयोग की अनुमति दे दी। अमेरिका इराक की सामरिक शक्ति को इस प्रकार घटाना व कमजोर करना चाहता था कि वह पश्चिम एशिया के किसी दूसरे राष्ट्र चुनौती देने की स्थिति में न रह पाए इसलिए 34 देशो की मिली-जुली 6,60,000 सैनिकों की भारी-भरकम फौज ने इराक के विरूद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। 17 जनवरी 1990 को बहुराष्ट्रीय लडाकू विमानों ने बगदाद पर भारी बमबारी की। ईराक को चारों तरफ से घेरा गया। इसे प्रथम खाडी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को -'ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्म' कहा जाता है । जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान नही था । अमेरिकी जनरल नार्मन श्वाजकॉव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशो की इस मिली जुली

सेना में 75 प्रतिशत सैनिक अमेरिका के ही थे । इराकी राष्ट्र सद्दाम हुसैन ने इसे 'सौ जंगों की एक जंग' कहा।

प्रथम खाडी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है । इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है । बडे विज्ञापनी अंदाज में अमरीका ने इस युद्ध में तथाकथित 'स्मार्ट बमो' का प्रयोग किया । इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे 'कम्प्युटर युद्ध' की संज्ञा दी।

खाडी युद्ध के बाद बदली परिस्थिति (अमेरिका वर्चस्व) की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 'नई विश्व व्यवस्था' की संज्ञा दी। बुश ने कहा कि इराक को पूर्ण रूप से कुवैत से सेना हटानी होगी । परन्तु इराक इजराइल व सउदी अरब पर स्कड प्रक्षेपात्रों से आक्रमण करता रहा । इस युद्ध की टीवी प्रोग्राम की तरह कवरेज की गई इसलिए इसे 'वीडियो वार गेम' भी कहा जाता है। युद्ध में अमेरिकी सफलता ने अमेरिका का वर्चस्व स्थापित किया।

<u>क्लिंटन का दौर</u> :- प्रथम खाडी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफर्सन (बिल) क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्योंकि अमेरीकी कार्रवाई की आलोचना हुई। इसे अमेरीकी दादागिरी माना गया।

क्लिंटन के दौर से ऐसा जान पडता था कि अमेरिका ने अपने आप को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उसकी भरपुर संलग्नता नही रही । विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी, कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढावे, जलवायु, परिवर्तन, तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया। यद्यपि बिल क्लिंटन के काल में अमेरिकी वर्चस्व के कतिपय उदाहरण हैः-

यूगोस्लाविया के विरूद्ध कार्रवाई 1999 में अपने प्रांत कोसोवों में युगोस्लाविया ने अल्बानिया लोगो के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाही की। इसके जवाब में अमरीकी नेतृत्व में नाटों के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर दो महिने तक बमबारी की। इससे कोसोवो में नाटों सेनाएं ठहरी और मिलोसेविच सरकार का पतन हुआ।

वर्तमान में युगोस्लाविया नामक देश नही है। यह कई देशों में विभाजित हो चुका है । ये देश है-स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, सर्बिया, मेसीडोनिया, मेटिनेग्रो एवे कोसोव ।

केन्या :-1998 में जब केन्या और दारे-सलाम तंजानिया में अमरीकी दूतावासों पर बमबारी हुई तो आतंकवादी संगठन अलकायदा को जिम्मेदार मानते हुए अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमले किये । इस सैन्य कार्यवाही को 'ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच' का नाम दिया गया। यह कार्रवाई क्लिंटन के आदेश पर की गई। अमेरिका ने अपनी कार्यवाही के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नही की ।

9/11 घटना-11 सितम्बर, 2001 के दिन विभिन्न अरब देशो के 19 अपहरणकर्ताओं ने उडान भरने के चंद मिनटों बाद चार अमरीकी व्यवसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। दो विमान न्यूयार्क स्थित 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए तीसरा विमान विर्जिनिया के अर्लिंगटन स्थित पेटागन से टकराया। पेंटागन में अमरीकी रक्षा-विभाग का मुख्यालय है चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। लेकिन वह पेन्सिलवेनिया के एक खेत में गिर गया । इस हमले में तीन हजार लोग मारे गए। इस हमले को ''नाइन एलेवन(9/11)'' कहा जाता है।

9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाये और भयंकर कार्यवाही की । जब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। 'आंतकवाद के विरूद्ध विश्वव्यापी युद्ध' के रूप में अमरीका ने ''ऑपरेशन एन्डयूरिंग फ्रीडम चलाया। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान-शासन को बनाया गया । 2 मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नौसेना की सील टीम ने ''ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर' नाम की सैन्य कार्यवाही में मार दिया गया। इस ऑपरेशन में प्रयुक्त कोड था-जेरोनिमों इकियो।

<u>इराक पर आक्रमण</u> :- सदाम हुसैन के तानाशाही शासन को समाप्त करने तथा सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए 19 मार्च, 2003 को अमेरीकी ने 'ऑपरेशन इराकी फ्रीडम' के कुटनाम से इराक पर हमला किया । अमेरिकी नेतृत्व वाले 'कॉअलिशन ऑफ वीलिग्स' (आकांक्षियों के गठजोड) में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। सदाम हुसैन की तानाशाही सरकार अमेरिका के इराक हमले के पश्चात समाप्त हो गई परन्तु अमेरिका ईराक को शांत नही कर पाया । इराक में अमेरिका के विरूद्ध एक पूर्णव्यापी विद्रोह भडक उठा । अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। UNO ने ये कहा था कि सामूहिक संहार के हथियार (वीपंस ऑफ मास डेस्ट्रक्शन) बनाने में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे । जैसे इराक के तेल-भण्डार पर नियंत्रण स्थापित करना और इराक में अमरीकी की मनपसंद सरकार की स्थापना करना।

अमेरिकी वर्चस्व

अमेरिकी वर्चस्व का युग 1991 में सोवियत संघ के विघटन से शुरू होता है जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दो महाशक्तियों में से अमेरिका ही मात्र महाशक्ति रह गया। अमेरिका अपनी पुरी ताकत के साथ खडा था। वह सबसे बडी सैनिक ताकत थी। यही वर्चस्व है। वर्चस्व शब्द प्राचीन यूनान से लिया गया। इसके लिए ''हेगेमनी'' शब्द का प्रयोग किया गया। ''हेगेमनी'' का अर्थ पहले राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तौल से होता है। इसका अर्थ किसी एक राज्य के नेतृत्व व प्रभुत्व से लिया जाता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यदि ताकत का केन्द्र एक ही हो तो उसे हेगेमनी या वर्चस्व कहते है। अमेरिका के लिए यह शब्द सैन्य प्राबल्य के लिए किया जाता है।

<u>वर्चस्व के निम्नलिखित तीन अलग-अलग अर्थ है</u> :-

1. <u>सैनिक वर्चस्व</u>:- अमेरीका की मौजूदा ताकत की रीढ उसकी बढी-चढी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में बाकी देशों की तुलना में बहुत अधिक है। वह विश्व के किसी भी देश को अपनी अपूर्व सैन्य क्षमता एवं ताकत के बल पर निशाना बना सकता है। उदाहरण के तौर पर इराक पर हमला, अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमलों के कारण आम नागरिक भी इसकी चपेट से बच नही पाए तथा इन हमलों में कई अपंग भी हो गए।

2. <u>ढांचागत ताकत के रूप में वर्चस्व</u> :- वर्चस्व का यह अर्थ, इसके पहले अर्थ से बहुत अलग है। ढांचागत वर्चस्व का अर्थ है- वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाना तथा अपने उपयोग की चीजों को बनाना व बनाए रखना अनेक ऐसे उदाहरण है जो यह स्पष्ट करते है कि अमेरीका का ढांचागत क्षेत्र में भी वर्चस्व कायम है। जैसे -छोटे-छोटे देशों में ऋणों में कटौती तथा उन पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाना आदि। अमेरीका उसकी बात न मानने वाले देशों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने में भी कामयाब रहता है।

3. <u>सांस्कृतिक वर्चस्व-विश्व में दो प्रमुख विचारधाराएं रही है</u> :- एक साम्यवादी विचारधारा व दूसरी पूंजीवादी विचारधारा। आज विश्व परिदृश्य पर नजर डाली जाए तो विश्व के अधिकतर देशों पर जबर्दस्ती पूंजीवादी विचारधारा थोप दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से अमेरीका यह स्पष्ट कर चुका है कि जो देश नई उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीति को नही अपनाएगा, उन देशों में बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियां निवेश

नही करेगा । विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक जैसी आर्थिक संस्थाओं में अमेरिका का वर्चस्व है।

अमरीकी शक्ति (वर्चस्व) के रास्ते में अवरोधः अमेरिका वर्चस्व के तीन अवरोध है

a. अमेरिका की संस्थागत बनावट

b. अमेरिका का उन्मुक्त समाज तथा जनसंचार के साधन

c. नाटो सैनिक संगठन

a. अमेरिका की संस्थागत बनावट :- अमेरिका वर्चस्व में पहला व्यवधान स्वयं अमरीका की संस्थागत बनावट है । यहा शक्तियों का विभाजन तीन अंगो में किया गया है। यह शक्ति विजाजन कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का काम करती है । राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। इन तीनों अंगो का समय में सक्षम होना तथा एक दूसरे पर नियंत्रण लगाना, अमेरिका में शक्ति संतुलन का काम करता है।

b. अमेरिका का उन्मुक्त समाज तथा जनसंचार के साधर :- अमेरिकी समाज अपनी प्रकृति से उन्मुक्त है । राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किसी कठोर कार्यवाही के लिए अमेरिकी नागरीकों को एकमत करना कठिन है । जनसंचार के साधनों पर निजी स्वामित्व होने से चाहे जनमत प्रभावित हो जाए, परन्तु अमेरिकी समाज की राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को सदैव संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अमेरिका सक्षम होने पर भी सैन्य शक्ति का प्रयोग सीमित करता है क्योकि जनता का विरोध विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाता है ।

c. नाटो सैनिक संगठन :- अमेरिका के मित्र देशों का पश्चिमी गठबन्धन जिसकी राजनीति अमेरिका से प्रभावित है उसके साथ मित्रता बनाए रखना ही अमेरिका के लोकतांत्रिक हित को पुरा करता है। अमेरिका शक्ति में तीसरा बडा अवरोध नाटों ही है। नाटो में शामिल लोकतांत्रिक देश अमेरिका की शक्ति संयमित रखने के लिए नैतिक दबाव डालते है । अतः नाटो की अमेरिकी मित्र देश अपनी शक्ति बढाते हुए अमेरिकी वर्चस्व की शक्ति पर अंकुश लगाते है।

इसके अतिरिक्त सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र भी अमेरिकी वर्चस्व पर अंकुश लगाते है। जैसे- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, यूरोपीय संघ, चीन का तीव्र उभार, ब्रिक्स (ब्राजील, भारत, चीन एवं द. अफ्रीका का संगठन), एल्बा, आसियान, विश्व सामाजिक संघ।

CELAC (Community of Latin American and Carribean States) लैटिन अमेरिका एवं केरिबियाई देशो का समूह है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 2010 को हुई इसमें 33 सदस्य देश हैं यह क्षेत्रीय समूह अमेरिकी वर्चस्व को चुनौति दे रहा है।

शब्दावली

द्विध्रुवीयता :- यह वह व्यवस्था है जिसमें विश्व दो गुटो में बंट गया। जैसे-द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात अमेरिका व सोवियत संघ के दो शक्तिगुट।

एकध्रुवीयता :- विश्व में केवल एक शक्ति का वर्चस्व होता है। जैसे वर्तमान में अमेरिका 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही विश्व में एकमात्र सैनिक, आर्थिक ताकत बन गया।

बहुध्रुवीयता :-शक्ति का दो से अधिक बडी शक्तियों में विभाजन

शॉक थेरेपीः- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा निर्देशित रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशो में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक विशेष मॉडल।

2. <u>संयुक्त राष्ट्र संघ</u>

(United Nation Organization)

- इसका विचार 1914 ई. में अटलांटिक चार्टर में रखा गया जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति (रूजवेल्ट) ने हस्ताक्षर किए।
- 26 जून 1945ई. को सेन फ्रांसिस्कों सम्मेलन में UN चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 ई. को लागू हुआ जिसे UN का स्थापना दिवस कहा जाता है।
- शुरूआती सदस्य 51 थे और वर्तमान सदस्य 193 है।
- 30 अक्टूबर 1995 ई. को भारत UN में शामिल हुआ।
- UN की 6 आधिकारिक भाषाएँ है।

1. अंग्रेजी	4. चीन
2. फ्रेंच	5. स्पेनिश
3. रूसी	6. अरबी

मुख्यालय - न्यूयॉर्क

- 2001 ई. में UN को शान्ति का नोबेल पुरस्कार दिया।

प्रथम विश्व युद्ध (1914–18) के बाद विश्व शांति स्थापित करने के प्रयास शुरू किये गए। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का हल आपसी बातचीत से निकालने और विश्व में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से 1920 में वुडरो विल्सन के प्रयासो से वर्साय संधि के आधार पर राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन) की स्थापना की गई। वर्साय संधि के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढाने और शांति तथा सुरक्षा प्राप्ति के लिये 1919 में ही राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। परन्तु 1 सितम्बर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान अपार जन धन की हानि हुई। इसलिये इस युद्ध के दौरान ही राष्ट्र संघ से कही अधिक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। अतः भावी पीढियों को युद्ध की विभिषिका से बचाने के लिये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई।

संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास (Evolution of UNO)

प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन, 1899 में द हेग (नीदरलैण्ड) में हुआ। जिसका उद्देश्य संकटों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने,युद्धों को रोकने और युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने के लिए दस्तावेजों को विस्तृत करना था इस आधार पर हेग में स्थायी न्यायालय स्थापित किया गया। जिसनें 1902 में काम करना शुरू किया। राष्ट्र संघ की विफलता के पश्चात् 'सुरक्षा सिद्धान्त' को महत्व देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शांति संगठन स्थापित करने के प्रयास तेज हो गये। सुरक्षा सिद्धान्त के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा स्थापित करना है ।

लंदन सम्मेलन (जून, 1941) :-

12 जून 1941 को लन्दन में ग्रेट ब्रिटेन, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पौलेंड युनान, दक्षिण अफ्रीका आदि राष्ट्रमंडलीय देशों ने शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का सुझाव दिया और एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह निश्चित किया गया कि हस्ताक्षरकर्ता देश आपस में तथा अन्य स्वतंत्र राष्ट्रो के साथ युद्ध और शांति दोनो में साथ मिलकर काम करेंगे ।

अटलांटिक चार्टर (14 अगस्त, 1941) :-

एक नई विश्व संस्था स्थापित करने के उद्देश्य से 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल अटलांटिक महासागर में कही एक जहाज पर मिले उन्होने एक संयुक्त घोषणा कि जिसे अटलांटिक चार्टर कहते है। इस चार्टर पर दोनो नेताओं ने हस्ताक्षर किये। इस चार्टर का उद्देश्य दोनों देशों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था । ई.एच. कार ने अपनी पुस्तक 'दो विश्व युद्धों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय संबंध' में कहा है कि यह चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना की दिशा में पहला कदम था ।

संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1-2 जनवरी, 1942) :-

1-2 जनवरी, 1942 ईस्वी की वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन एवं धूरी शक्तियों के विरूद्ध लड रहे सहयोगी राष्ट्र अटलांटिक चार्टर को सहमति प्रदान करने तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु इकट्ठे हुए । 26 राष्ट्रो के संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए अटलांटिक चार्टर को स्वीकार किया। । इसके पश्चात 11 दिसम्बर 1941 को धुरी राष्ट्रो ने अपनी त्रि-राष्ट्रीय समझौते की पुष्टि करते हुए युद्ध के बाद एक नई व्यवस्था स्थापित करने

की घोषणा की इसके जवाब में मित्र राष्ट्रो ने संयुक्त राष्ट्रो की घोषणा जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के आग्रह पर धुरी राष्ट्रों से संघर्षरत राष्ट्रो को संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग ''डिक्लेरेशन बाई यूनाइटेड नेशन्स'' (संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा) में 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था ।

मास्को घोषणा (अक्टूबर, 1943) :-

यह सम्मेलन 30 अक्टूबर 1943 को मास्को में हुआ । जिसमें विश्व में शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया । मास्को सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन ने घोषणा पर हस्ताक्षर करके यह निश्चित किया कि ''अपने देशों और दूसरे साथी मनुष्यों की स्वतंत्रता को आक्रमण के भय से सुरक्षित करने के उत्तरादायित्वों को पहचान कर युद्ध को शीघ्र समाप्त कर और हथियारों पर कम से कम व्यय करके अन्तर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की आवश्यकताओं को पहचान कर वे यह घोषणा करते हैं । उन्होंने शत्रुओं के विरूद्ध जो संयुक्त कार्य किए हैं उस तब तक करते रहेंगे जब तक शांति और सुरक्षा स्थापित न हो जाए ।'' ई.एच. कार के अनुसार ''इस निर्णय के आधार पर ही वास्तव में आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई ।'' वास्तव में एक घोषणा में राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का शिलान्यास किया गया ।

तेहरान सम्मेलन (नवम्बर-दिसम्बर, 1943) :-

तेहरान सम्मेलन 1 दिसम्बर 1943 को ईरान की राजधानी तेहरान में बुलाया गया । इस सम्मेलन का महत्व अधिक था। क्योंकि इसमें दोनों महाशक्तियों ने एक साथ हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने हिस्सा लिया। 1 दिसम्बर 1943 को अमेरिका, ब्रिटेन व रूस तीनों देशो के राज्याध्यक्षों ने हस्ताक्षर कियें ।

डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन (अक्टूबर, 1944) :-

21 अगस्त से 7अक्टूबर, 1944 के बीच अमरिका के वाशिंगटन के डम्बार्टन ओक्स भवन में दो भागों में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले भाग में अमरिका, ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और दूसरी बार दो महीने के पश्चात पहली बार विश्व के तीन महान नेता स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल तेहरान में पहली बार एक दूसरे से मिले और तीनों ने स्थायी शांति की स्थापना करने व उसको बनाये रखने के लिए दृढ संकल्प प्रकट किया। दूसरी बार 7 अक्टूबर, 1944 को रूस के स्थान

पर चीन का प्रतिनिधि शामिल हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगो की रूपरेखा तैयार की गई।

<u>याल्टा सम्मेलन (4-11 फरवरी, 1945) :-</u>

विश्व के तीन सबसे बडे नेताओं स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल 4 से 11 फरवरी, 1945 को सोवियत संघ के अधिकार वाले क्रीमिया में दूसरी बार एकत्रित हुए। इससे पहले 1 दिसम्बर 1943 को तेहरान सम्मेलन में मिले थे। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, उसकी सदस्यता एवं प्रकृति पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन की उन सभी बातों पर निर्णय लिया गया, जिन पर मतभेद थे। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद के 5 स्थाई सदस्यों और उनके निषेधाधिकार का निर्णय लिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सेन फ्रांसिस्कों में एक सम्मेलन 25 अप्रैल, 1945 को बुलाया निश्चित किया गया।

<u>सेन फ्रांसिस्कों सम्मेलन (25 अप्रैल से 26 जून, 1945) :-</u>

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अन्तिम रूप देने के लिए संयुक्त राज्य अमरिका के सेन फ्रासिस्कों में 25 अप्रैल, 1945 को एक सम्मेलन शुरू हुआ। जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अमरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का निधन हो जाने के कारण नये राष्ट्रपति ट्रूमेन ने उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लार्ड हैलीफैक्स ने की ।

इस सम्मेलन में भारत भी शामिल था । भारत की ओर से विदेश सचिव गिरिजा शंकर वाजपेयी ने भाग लिया। दूसरे प्रतिनिधि मण्डल के रूप में श्रीमति विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार किया गया। इस चार्टर पर 26 जून, 1945 को विश्व के 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये। कुछ माह पश्चात पोलैण्ड ने इस पर हस्ताक्षर किए और वह भी मूल सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल सदस्य संख्या 51 थी । 10 फरवरी, 1946 को लंदन के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की बैठक हुई । इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव हुआ ।

<u>संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर (UNO Charter) :-</u>

चार्टर का प्रारूप 14 अगस्त, 1941 को तैयार किया गया । संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर (विधान) को 26 जून, 1945 को अमरिका के सेन फ्रांसिस्कों नगर में स्वीकार किया गया । इस चार्टर के प्रावधानों

को अन्तिम रूप देकर उस पर 51 देशो ने हस्ताक्षर किये । इस चार्टर में कुल 111–अनुच्छेद, 19 अध्याय, राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में कुल 26 धाराएँ, 10,000 शब्द शामिल है । चार्टर में संयुक्त राष्ट्र की संगठन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य आदि की विशुद जानकारी मिलती है। यह चार्टर 24 अक्टूबर, 1945 को लागू हुआ ।

उद्देश्य :-

- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाए रखना ।
- मानवाधिकारों को बढावा देना ।
- वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए साझा प्रयास करना ।
- विश्व में आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक सहयोग स्थापित करना ।

UN की संरचना :-

1. महासभा (General Assembly)
2. सुरक्षा परिषद (General Assembly)
3. सचिवालय (Secratariat)
4. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic & Social Council)
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)
6. न्यास परिषद (Trusteeship Council)

1. महासभा (General Assembly) :-

- यह मुख्य चर्चा करने वाली संस्था है ।
- इसके द्वारा गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं ।
- इसके द्वारा चुनाव का कार्य भी किया जाता है –

जैसे:-

1. नए सदस्यों को शामिल करना ।
2. सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव
3. महासचिव का चुनाव
4. आर्थिक व सामाजिक परिषद के सभी सदस्यों का चुनाव
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी न्यायाधिशों का चुनाव

- UN का बजट महासभा के द्वारा पारित किया जाता है ।
- सभापति सदस्य देशों में से ही <u>एक वर्ष</u> के लिए चुना जाता है ।
- सितम्बर माह में इसकी एक (वार्षिक) बैठक आयोजित की जाती है ।

2. <u>सुरक्षा परिषद (Security Council)</u> :-

- यह UN की सबसे शक्तिशाली संस्था है जो कि अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव पारित कर सकती है ।
- इसके पास सैन्य हस्तक्षेप तथा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार होता है ।
- कुल सदस्य 15 है जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है ।

स्थायी सदस्य :-

1. USA
2. UK
3. France
4. China
5. Russia

- 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षो के लिए क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है ।
- 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका से, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप तथा 1 सदस्य लेटिन अमेरिका से है ।
- स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति दी गई है अर्थात कोई भी निर्णय इन सभी देशों की सहमति के बिना नही लिया जा सकता है ।

3. <u>सचिवालय (Secretariat)</u> :-

मुख्यालय - न्यूयॉर्क

- यह UN की नौकरशाही है ।
- इसका कार्य है बैठकों का आयोजन करना निर्णयों को लागू करना, रिपोर्ट जारी करना, बजट तैयार करना ।
- इसके प्रमुख को महासचिव कहा जाता है ।
- कार्यकाल 5 वर्ष
- वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुतेरस (पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री)

4. <u>आर्थिक एवं सामाजिक परिषद</u> :-

सदस्य - 54

कार्यकाल - 3 वर्ष

- विश्व में आर्थिक व सामाजिक सहयोग स्थापित करना है ।

- UN से सम्बन्धित विशेषीकृत एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है -

जैसे -

a) विश्व बैंक

b) IMF

c) WHO

d) विश्व मौसम संगठन

e) UNESCO

f) खादय एवं कृषि संगठन आदि

- कुछ आयोग भी बनाए गए है जैसे - जनसंख्या नियंत्रण, महिला सशक्तीकरण, सतत विकास आदि ।

5. <u>अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय</u> :-

मुख्यालय - हेग (नीदरलैण्ड)

न्यायाधीश - 15

कार्यकाल - 9 वर्ष

- कार्य - विवादों का निपटारा और कानूनों की व्याख्या

- भारत की तरफ से वर्तमान में दलवीर सिंह भण्डारी न्यायाधीश है ।

- सभी स्थायी देशों से 1-1 न्यायाधीश निर्वाचित तथा लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका व एशिया महाद्वीपो को योजना में प्रतिनिधित्व

6. <u>न्याय परिषद</u> :-

- 1994 ई. में निष्क्रिय है । (पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद)

- पूर्व में मेण्डेट व्यवस्था के क्षेत्र इसके अधीन थे ।

UN की सफलताएँ :-

1. तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सफल रहा है ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए UN के द्वारा अब तक 72 शान्ति मिशन भेजे गए है-
   जैसे- सोमालिया, सूडान, कोंगो, यूगांडा, रवांडा, कोरियाई युद्ध आदि ।
3. मानवाधिकारों को प्रचारित किया गया ।
4. 10 दिसम्बर 1948 ई. को मानवाधिकार की घोषणा-पत्र जारी किया गया । इसलिए 10 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ।
5. नाभिकीय शक्ति के प्रसार को रोकने के लिए NPT और CTBT जैसी सन्धियाँ की गई ।
6. जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पृथ्वी सम्मेलन (1992) Kyoto Protocol (1997), पेरिस सन्धि (2015) किया गया ।
7. सदस्य देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कार्य किए गए ।
8. मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए मानव विकास रिपार्ट (HDR) और मानव विकास सूचकांक (HDI) जारी किए जाते हैं ।
9. विश्व के विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) बनाए गए हैं ।
   (17 – Goals, 169 - Targets)

UN की असफलताएँ :-

1. शीतयुद्ध के काल में गुटवाद, शस्त्रीकरण और सैन्यीकरण को बढावा दिया गया ।
2. UN शीतयुद्ध को रोकने में असफल रहा ।
3. UN स्वयं का लोकतंत्रीकरण करने में असफल रहा ।
4. अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नही है ।
5. आतंकवाद के विरूद्ध सशक्त कार्यवाही करने में असफल रहा, यहां तक की आतंकवाद को परिभाषित भी नही कर सका है ।
6. सुरक्षा परिषद के सैन्य हस्तक्षेपों का प्रयोग शक्तिशाली देशों की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है ।
   जैसे - लीबीया में सैन्य हस्तक्षेप

7. नाभिकीय हथियार आज भी विश्व के सामने एक बडी समस्या है ।

8. UN की सन्धियाँ भेदभावपूर्ण है ।

9. नए देश नाभिकीय शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं ।

जैसे- उत्तरी कोरिया

10. UN बजट के लिए आत्मनिर्भर नही है । बजट में सर्वाधिक योगदान USA (22%) और जापान के द्वारा किया जाता है ।

11. वर्तमान के ज्वलन्त मुद्दे जैसे - सिरियाई संकट, यमन संकट, यूक्रेन संकट, शरणार्थी संकट आदि को हल करने में UN असफल रहा है ।

UN में सुधार की प्रक्रिया :-

- UN में किसी भी बडे सुधार के लिए UN चार्टर में संशोधन आवश्यक है ।
- इसके लिए सर्वप्रथम एक प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में लाया जाना चाहिए जहाँ 2/3 मत से पारित हो स्थायी सदस्यों सहित ।
- तत्पश्चात यह प्रस्ताव महासभा में लाया जाएगा जहाँ यह 2/3 मतों से पारित होना चाहिए ।

UN में सुधार :-

- UN में संरचनात्मक सुधार करते हुए सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाना चाहिए ।
- सुरक्षा परिषद वर्तमान की राजनीतिक स्थिति को दर्शाती नही है ।
- महासभा की शक्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए ।
- UN के निर्णयों और कार्यो में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए ।
- बजट सम्बन्धी सुधार लागू किए जाने चाहिए ।
- बजट के लिए UN को आत्मनिर्भर बनना चाहिए ।
- UN को अपने सुरक्षा सम्बन्धी कार्यो को सीमित करना चाहिए तथा विकासात्मक गतिविधियों पर आर्थिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ।